अहमदाबाद के नए मानसिक अस्पताल कम्पलेक्स में फर्नीचर वाटर-कूलर और टेलीफोन की सुविधाओं से लैस परिसर आवंटित किया गया है;

(ख) क्या यह भी सच है कि इस परिसर का एक वर्ष से भी अधिक समय तक महालेखाकार के कार्यालय द्वारा इस्तेमाल नहीं किया गया और यह कार्यालय गैर-सरकारी परिसर में किराए पर चलता रहा; और

(ग) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

वित्त मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री जनार्दन पुजारी) : (क) जी हां । लेकिन राज्य सरकार द्वारा फर्नीचर वाटर-कूलर और टेलीफोन की सुविधाएं नहीं प्रदान की गई थीं ।

(ख) जी, नहीं । यह भवन 23 फरवरी 1984 को लिया गया था । और इसे उस अतिरिक्त काम के लिए तैनात किये जाने वाले अधिकारियों के लिए स्थान की व्यवस्था किये जाने के लिए इस्तेमाल किया जाना था जो 1 मार्च, 1984 से भारतीय लेखा परीक्षा और लेखा विभाग में पुनर्संरचना स्कीम के कार्यान्वयन के परिणामस्वरूप तथा पुनर्संरचना के कारण कुछ अन्य कार्यों की व्यवस्था करने के लिए महालेखाकार गुजरात राजकोट के कार्यालय से स्थानान्तरित किया गया था । राजकोट कर्मचारी संघ द्वारा सिविल मुकदमा दर्ज किये जाने के कारण राजकोट से अहमदाबाद का कार्यों तथा रिकार्डों का स्थानान्तरण रहा । इसलिए 29 अगस्त 1984 तक भवन का कब्जा नहीं लिया जा सका । यह कानूनी बाधा 28 अगस्त, 1984 को समाप्त हुई जिसके पश्चात् भवन का कब्जा अगस्त अगले दिन अर्थात् 29 अगस्त, 1984 को लिया गया । चूंकि कार्य के किसी भाग तथा उसमें उक्त भवन में रखे गए रिकार्ड को न्यू मैन्टल हास्पिटल कौम्पलैक्स में स्थानान्तरित नहीं किया जाना था इसलिए अहमदाबाद में गैर-सरकारी आधार पर किराये पर लिये गये परिसर पर कब्जा जारी रखना था ।

(ग) उपर्युक्त (क) और (ख) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता ।

Peerless General and Investment Company

1889. SHRI KALPNATH RAI: Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) whether Government have received any request from the employees' union of the Peeress General and Investment Company to nationalise that company; and

(b) if so, what decision Government have taken thereon?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF FINANCE (SHRI JANARDHAN POOJARI): (a) Yes, Sir.

(b) In terms of the provisions of Prize Chits and Money Circulation Schemes (Banning) Act, 1978, the Peerless General Finance and Investment Co. Ltd. was served with a notice on August 10, 1979 by the Government of West Bengal who are entrusted with the implementation of the provisions of the Banning Act, to wind up its business. The company filed a writ petition in the High Court of Calcutta on September 3, 1979 challenging the applicability of the Act to its business and obtained stay. Union Government and Reserve Bank of India and the Government of West Bengal are the Respondents in the Writ Petition. The matter is still pending in the Court.

Letters from MPs, pending before Central Board of Direct Taxes

1890. SHRI V. GOPALSAMY:
SHRI L. GANESAN:

Will the Minister of FINANCE be pleased to state:

(a) the number of letters received from Members of Parliament which are still pending before the Central Board of Direct Taxes;

(b) How many such letters are pending for more than 3 months, how many are pending for more than 6 months but less